



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, ब्रह्मस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2010/अग्रहायण 18, 1932

No. 308]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2010/AGRAHAYANA 18, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2010

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सैकेरिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 15/20/2010-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदप्रचात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सैकेरिन (जिसे एतदप्रचात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक परिणाम दिनांक 1 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 14/27/2004-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 6 जून, 2006 की अधिसूचना सं. 54/2006-सीमा-शुल्क द्वारा अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था। प्राधिकारी की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 14/27/2004-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित की गई थी। अंतिम जांच परिणामों के आधार पर राजस्व विभाग की दिनांक 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 41/2007-सीमा-शुल्क द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 15/15/2008-डीजीएडी द्वारा मध्यावधि समीक्षा जाँच (एमटीआर)

की शुरुआत की गई थी। दिनांक 6 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 15/15/2008-डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा एमटीआर की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। प्राधिकारी के एमटीआर संबंधी अंतिम जांच परिणामों में की गई सिफारिशों के अनुसरण में राजस्व विभाग ने दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 को सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 136/2009-सी.शु. जारी की थी।

2. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

यतः सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी सं. 2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतदद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार वह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

3. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा जाँच में विचाराधीन उत्पाद सैकेरिन है।

(क) सैकेरिन एक अपोषक स्वीटनर है और इसे चीनी का कम कैलोरी वाला विकल्प माना जाता है। सैकेरिन का उत्पादन मुख्यतः दो रूपों में किया जाता है, अर्थात् घुलनशील और अघुलनशील सैकेरिन। बाजार की भाषा में घुलनशील सैकेरिन को सोडियम सैकेरिन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सोडियम सैकेरिन को अघुलनशील सैकेरिन कहा जाता है।

सोडियम सैकेरिन के अलावा सैकेरिन के अन्य रूप भी होते हैं जैसे कैल्शियम और जिंक सैकेरिन। सैकेरिन का उत्पादन दो भौतिक स्वरूपों अर्थात् रवेदार और पाउडर में किया जाता है। रवेदार रूप में सोडियम सैकेरिन का इस्तेमाल उन परिस्थितियों में किया जाता है जिनमें सैकेरिन को द्रवीभूत किया जाना होता है। पाउडर रूप में सैकेरिन जिसे पीसा और स्प्रे ड्राई किया जाता है, का इस्तेमाल सूखे मिश्रणों और भेषज में किया जाता है सैकेरिन के अघुलनशील रूप का इस्तेमाल कई प्रकार के भेषजों और चिकित्सकीय अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है। चीनी की तुलना में सैकेरिन 500 गुना अधिक मीठी होती है। सैकेरिन के सभी रूप मौजूदा जाँच के दायरे में शामिल हैं।

- (ख) सैकेरिन का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे-खाद्य एवं धैय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टॉप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषज आदि में किया जाता है।
- (ग) सैकेरिन सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की शाष सं. 2925 11 00 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और संबद्ध जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

4. प्रक्रिया

इस जाँच से यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क की समाप्ति या उसमें परिवर्तन या दोनों ही किए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है :

- (i) इस समीक्षा में दिनांक 3-1-2007 की अधिसूचना सं. 14/27/2004-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे। इस समीक्षा जाँच में शामिल देश चीन जन.गण. है।
- (ii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 01 अप्रैल, 2009 से 30 जून, 2010 (15 माह) है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2006—मार्च, 2007, अप्रैल 2007—मार्च 2008, अप्रैल 2008—मार्च 2009 तथा प्रस्तावित जाँच अवधि शामिल होगी।
- (iii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

5. सूचना प्रस्तुत करना

घरेलू उद्योग द्वारा शुल्क का अधिरोपण जारी रखने की आवश्यकता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु आवेदन) में इस आशय से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि पहले से लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

संबद्ध देश के नियतकों और भारत स्थित उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, भारत में जात समझे जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से

अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 243
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकारों हेतु उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

6. समय सीमा

घरेलू उद्योग से सूचना प्रस्तुत होने पर, सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हों, को इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर ऊपर डिलायित पते पर प्राधिकारी को लिखित में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध न हों, भी घरेलू उद्योग के आवेदन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ आवेदन के अगोपनीय रूपांतर को सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

7. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND
ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2010

(Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset review of Anti-dumping duty imposed on imports of 'Saccharin' originating in or exported from China PR.

F. No. 15/20/2010-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles

and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of 'Saccharin' (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country). The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/27/2004-DGAD dated 1st April, 2006 and the interim anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 54/2006-Customs dated 6th June, 2006. The final findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/27/2004-DGAD dated 3rd January, 2007. On the basis of the final findings, definitive anti-dumping duty on the subject goods imported from the subject country was imposed by the Department of Revenue vide notification No. 41/2007-Customs dated 19th March, 2007. A mid-term review (MTR) was initiated by the Authority vide Notification No. 15/15/2008-DGAD dated the 7th May, 2008. The final findings notification of the MTR was issued by the Authority vide Notification No. 15/15/2008-DGAD dated 6th November 2009. Pursuant to the recommendations in the MTR final findings of the Authority, the Department of Revenue had notified the Customs Notification vide No. 136/2009-Customs dated 9th December, 2009.

2. Initiation of Sunset Review

Whereas in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, the anti-dumping duties imposed, shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No. 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory. Therefore, pursuant to the above orders of the Hon'ble High Court, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Anti-dumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. Product under Consideration

The product under consideration in the present investigation is Saccharin :

(a) Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Saccharin is primarily produced in two types i.e. soluble and insoluble saccharin. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin, whereas insoluble sodium saccharin is called insoluble saccharin. Apart from sodium saccharin, saccharin can have other variants such as calcium and zinc saccharin. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situation where saccharin will be dissolved, the powder form which have been grounded and spray dried is used

in dry mixes and pharmaceuticals. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. It is slightly soluble in water. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation.

- (b) Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc.
- (c) Saccharin is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No. 29251100. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigations.

4. Procedure

The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both :—

- i. The review will cover all aspects of Notification 14/27/2004-DGAD dated 3rd January, 2007. The country involved in this review investigation is China PR.
- ii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st April, 2009 to 30th June, 2010 (15 months). The injury investigation period will however cover the periods, April 2006 to March 2007, April 2007 to March 2008 and April 2008 to March 2009 and the proposed POI.
- iii. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

5. Submission of Information

The Domestic industry is required to submit information on prescribed proforma (Application for Domestic industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty within Forty Days (40 days) of issue of this notification.

The exporters in subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 243

Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any

party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

6. Time Limit

On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from the date of application from Domestic industry. For this purpose non-confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the

Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

7. Inspection of Public File

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority